यह कहा है कि 3928 मौतें प्रमाणित हुई हैं। लेकिन दस हजार रुपये की जो राशि दी गयी है वह केवल 3540 लोगों को दी गयी है। तो शेष लोगों को राशि वितरण क्यों नहीं हुआ, जबकि यह मौतें पांच वर्ष पूर्व प्रमाणित हो चुकी हैं?

दूसरा भाग यह है कि अन्तरिम राहत कब तक चलती रहेगी और कब तक इसका अंतिम निर्णय हो जायेगा, क्योंकि पांच लाख लोगों को दो सौ रुपये प्रति माह अंतरिम राहत दे रहे हैं, तो अंतिम रूप से इसका निर्णय कब तक हो जायेगा?

SHRI CHINTA MOHAN: This is due to the side-effect of the MIC gas. Soon after receiving the recommendations from the counsel of the people, the State Government is ready to give them compensation.

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर: आदरणीय सभापति महोदय, भोपाल गैस त्रासदी सन् 1984 में हुई थी। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर गैस पीड़ितों के लिये उचित कदम उठाये और उनको रिलीफ देने का प्रयास किया और काफी कुछ रिलीफ प्रदान किया गया। लेकिन दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार मौजूद है, उसकी द्वारा लापरवाही के कारण गैस पीड़ितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भोपाल के गैस पीड़ितों... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब प्रश्न कर लीजिये। उन्होंने कहा है कि जितने प्रश्न हैं, वह सबके साथ इक्ट्ठे बैठकर बात कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर: मैं माननीय प्रधान मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाया जाये और मेरा इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है— उस समय की वर्तमान सरकार ने वायदा किया था कि जितने भी कर्मचारी वहां यूनियन कार्बाइड में काम करते थे, उनको राज्य सरकार अपनी तरफ से सर्विसिज का इंतजाम करेगी या रोजगार की कोई व्यवस्था करेगी? तो मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी बाकी है जिनका रिहैबिलिटेशन अभी तक नहीं हो पाया है और उनके लिये क्या योजना है?

SHRI CHINTA MOHAN: The State Government is taking all possible efforts. So far they have spent about Rs. 297 crores for all these victims. They are waiting for the decision of the Supreme Court. Soon after receiving the....

SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: I am sorry, the Hon'ble Minister did not understand my question. My question was regarding the workers who were working in the Union Carbide before the incident took place.

SHRI CHINTA MOHAN: We will examine it. Whatever is to be done, we will do.

Mr. CHAIRMAN: Question No. 246-A.

*246A. [*The Questioners (Sardar Jagjit Singh Aurora and Dr. Jinendra Kumar Jain) were absent. For answer vide cols. 45-46 infra*].

Special Assistance to Bombay under the Gadgil Formula

*247. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to grant special central assistance under the Gadgil formula to Bombay city for infrastructural facilities like Power, Water, Housing, Roads, Transport and Sanitation etc; and

(b) if so, the details thereof; if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Annual Plan for Maharashtra (1991-92) was approved at Rs. 2500 crores, with criteria based normal Central assistance (gross) of Rs. 380.31 crore (including Central assistance for special problems of the State). Furthermore it was agreed that the outlay could be enhanced to Rs. 3000 crores, subject to additional resources of Rs. 500 crores (including Rs. 75 crores for Bombay city, comprising of Rs. 50 crores as Central assistance and Rs. 25 crores as additional Central transfers) to be raised by the State and Central Governments together.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

—

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial growth in West Bengal

*242. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have been discussing with the Government of West Bengal the matter relating to industrial growth in the State and that of pending projects which are still awaiting clearance of the Central Government;

(b) whether any headway has been made so far;

(c) whether delay is causing enormous losses both in terms of production and employment potentialities in the State; and

(d) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Conceptualisation and implementation of projects is an ongoing exercise requiring coordination between various agencies of the State and Central Government. A number of projects in West Bengal have been cleared and we are in constant dialogue with them for effective and expeditious implementation.

राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण

*243. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किन्हीं मराठी फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन पर करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) रविवार अपराह्न राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाए जाने के लिए दूरदर्शन द्वारा उन फीचर फिल्मों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, जिन्होंने निम्नलिखित वर्गों में से कोई भी राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया हो:

1. सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राज्य पुरस्कार

2. सर्वोत्तम निर्देशन के लिए राज्य पुरस्कार

3. किन्हीं दो राज्य पुरस्कारों से पुरस्कृत फिल्में।

(ग) जी, हां।